भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1861
उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026

तमिलनाडु के ग्रामीण, दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल टावर

1861. श्री जी. सेल्वमः
श्री नवसकनी के.:
श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने डिजिटल भारत निधि के माध्यम से तमिलनाडु के ग्रामीण, दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित किए हैं और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान जिलेवार और ब्लॉकवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त निधि के तहत धनराशि आवंटित किए जाने के बावजूद तमिलनाडु के जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सी बसावटों में खराब मोबाइल कनेक्टिविटी है या मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे टावरों के चालू होने के बाद वॉयस और डेटा सेवाओं में वास्तविक सुधार का मूल्यांकन करने के लिए कोई स्वतंत्र आकलन किया गया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या रहे; और

(घ) राज्य में जनजातीय समुदायों के लिए समय पर निर्माण कार्य पूरा करने, बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग करने और विश्वसनीय मोबाइल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) सरकार ने डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के माध्यम से तमिलनाडु सहित देश के ग्रामीण दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल टावर चालू किए हैं। तमिलनाडु में पिछले पांच वर्षों के दौरान चालू किए गए मोबाइल टावरों की संख्या डीबीएन की वेबसाइट **(https://usof.gov.in/en/home)** पर उपलब्ध है।

(ख) तमिलनाडु के 248 जनजातीय गांवों में से 246 गांवों में मोबाइल कवरेज मौजूद है।

(ग) डीबीएन के माध्यम से टावर चालू करने के बाद विनिर्देशों की अनुरूपता का सत्यापन करने के लिए तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया जाता है।

(घ) सरकार मोबाइल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए नियमित आधार पर विभिन्न केंद्रीय/राज्य एजेंसियों के साथ सुधारात्मक कदम उठाती है।

*****